



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III — Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]
No. 186]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2007/भाद्र 26, 1929
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2007/BHADRA 26, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2007

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007

(2007 का संख्यांक 9)

फा. सं. 4-54/2007-बी एंड सीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
की अधिसूचना सं. 39 जो,—

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45(अ) दिनांक 9 जनवरी, 2004 के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) तथा उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा तथा धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन

विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये 1 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में, खंड 2 में, —

(i) उप-खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(कक) “अधिनियम” से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;’

(ii) उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(िक) “बाणिज्यिक सब्सक्राइबर” से अभिप्रेत है ऐसा सब्सक्राइबर जो उसके द्वारा सेवा प्रदाता को बताए गए स्थान पर कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है, तथा वह ऐसी सेवा के सिगनलों का प्रयोग अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्यों अथवा ऐसे स्थान तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या समूह के लाभ के लिए करता है;’

(iii) उप-खंड (ट) में, “केयू बैंड में” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(टक) “डायरेक्ट-टु-होम सेवा” से अभिप्रेत है किसी मध्यस्थ, जैसे केबल ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों का कोई अन्य वितरक, के माध्यम से संप्रेषण बिना सब्सक्राइबरों के परिसरों को सीधे टीवी सिगनल प्रदान कर एक उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करके बहु-चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण;’

(टख) "डायरेक्ट-टु-होम सब्सक्राइबर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट-टु-होम सेवा के सिगनल प्राप्त करता है;

(v) उप-खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(डक) 'साधारण सब्सक्राइबर' से ऐसा सब्सक्राइबर अभिप्रेत है जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रमों सेवा करता है और उनका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है;

'(डख) 'पे चैनल' से अभिप्रेत है ऐसा चैनल जिसके लिए केबल के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से इलैक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों द्वारा सिगनलों के ऐसे रि-ट्रांसमिशन के लिए प्रसारक से चैनल के सिगनल प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रसारक को शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसका आशय सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना है।

(डग) "कार्यक्रम" से कोई टेलीविजन प्रसारण अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है—

(i) वीडियो कैसेट रिकॉर्डरों अथवा वीडियो कैसेट प्लेयरों के माध्यम से फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण, तथा 'कार्यक्रम सेवा' अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार निकाला जाएगा;

(vi) उप-खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(डक) 'सब्सक्राइबर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा प्रदाता से उसके द्वारा बताए गए किसी स्थान पर उस सेवा प्रदाता के सिगनल प्राप्त करता है और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को आगे ट्रांसमिट नहीं करता है तथा इसमें साधारण सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर दोनों ही शामिल हैं, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से हटाया न गया हो;

3. प्रधान विनियम के विनियम 13 में, —

(क) उप-विनियम 13.1 में, "13.1 सभी प्रसारक" अंकों तथा शब्दों से आरंभ होने वाले प्रारंभिक स्थान में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"गैर-एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव

13.1 सभी प्रसारक" ;

(ख) उप-विनियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"13.2क डायरेक्ट-टु-होम सेवा के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव

13.2क.1 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथी संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, उस तारीख को विद्यमान और नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अस्तित्व में आने वाले सभी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को, उसका संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निबंधन और शर्तों सहित डायरेक्ट-टु-होम प्लेटफार्म हेतु अंतरसंयोजन के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया होगा, अर्थात्:—

(क) अला-कार्टे आधार पर चैनलों की दरें तथा प्रसारक द्वारा डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को प्रदान किए जा रहे बुके की दरें;

(ख) छूट के विवरण, यदि कोई है;

(ग) भुगतान की शर्तें;

(घ) प्रतिभूति तथा प्रति-चौर्य आवश्यकताएं;

(ङ) सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सब्सक्राइबर रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षा;

(च) करार की अवधि;

(छ) करारों का समापन;

13.2क.2 प्रत्येक प्रसारक, अपनी वेबसाइट पर, उप-विनियम, 13.2क.1 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव की एक प्रति प्रकाशित करेगा:

परंतु यह कि कोई प्रसारक, जिसने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व कोई संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर सूचित अथवा प्रकाशित किया है, वह ऐसे संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को परिवर्धित करेगा ताकि यह प्रस्ताव विनियम 13.2क.1 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप बन सके और उसे प्रकाशित करेगा जैसा कि इस उप-विनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

13.2क.3 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् प्रसारण सेवाएं उपलब्ध करना शुरू करता है, ऐसे प्रारंभ के नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, जो भी बाद में हो, उस तारीख को विद्यमान सभी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को, उसका संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा जिसमें उप-विनियम 13.2क.1 में निर्दिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट होंगी तथा इसे ऐसी सूचना से पूर्व अथवा उसके साथ-साथ इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

13.2क.4 प्रत्येक डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक, जिसे दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् लाइसेंस प्रदान किया गया है, किसी प्रसारक को ऐसे प्रसारक के संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकेगा तथा ऐसा प्रसारक, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर, वह प्रति डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को उपलब्ध कराएगा।

13.2क.5 प्रत्येक प्रसारक, जो उप-विनियम 13.2क.1 अथवा उप-विनियम 13.2क.3 में निर्दिष्ट इसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में कोई परिवर्धन करता है, ऐसे परिवर्धनों के तत्काल बाद, इसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में किए गए ऐसे परिवर्धनों के बारे में सभी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को सूचित करेगा।

परंतु यह कि ऐसे सभी परिवर्धन उसी शीति से उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित तथा प्रदर्शित किए जाएंगे जैसे कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को सूचित किया गया था तथा प्रसारकों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

प्रसारकों और डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों के बीच करार

13.2क.6 (1) खंड 13.2क.1 अथवा 13.2क.3 अथवा 13.2क.5 में निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, तथा डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को सूचित तथा प्रसारक द्वारा इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किसी प्रसारक का संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव, प्रसारक तथा डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों के बीच किए जाने वाले सभी अंतरसंयोजन करारों का आधार होगा:

परंतु यह कि प्रसारक विभिन्न डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों के साथ ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो उनके बीच सहमत की जाएंगी, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को परिवर्धित करके, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, करार कर सकेंगे।

परंतु यह और कि यदि किसी प्रसारक ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक के साथ करार किया है और वह उक्त विनियमों के अंतर्गत उसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (उसके संवर्धनों सहित) को बाद में प्रकाशित करता है, तो ऐसा प्रसारक, उक्त प्रस्ताव के प्रकाशन के पश्चात, ऐसे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को या तो इन विनियमों के अनुरूप कोई करार करने अथवा ऐसे प्रारंभन से पूर्व किए गए करार को उसकी वैधता तक जारी रखने का विकल्प देगा।

(2) कोई प्रसारक, जिसने, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक के साथ करार किया है तथा ऐसे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक ने ऐसे प्रारंभन के पश्चात प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप ऐसे प्रसारक के साथ करार करने के लिए उप-नियम (1) के अंतर्गत विकल्प दिया है, ऐसी तारीख, जिसको ऐसे प्रचालक ने

विकल्प दिया है, से प्रारंभ होने वाली, तथा ऐसी तारीख, जिसको संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप ऐसा करार किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अथवा पूर्व करार की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले थी, सिगनलों को विच्छेदित (इन विनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप के सिवाए) नहीं करेगा।

(3) कोई प्रसारक, जिसने, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक के साथ करार किया है तथा ऐसे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक ने ऐसे प्रारंभ से पूर्व, ऐसे प्रसारक के साथ, किए गए करार को जारी रखने के लिए उप-विनियम (1) के अंतर्गत विकल्प दिया है, ऐसे करार की वैधता के दौरान ऐसे प्रचालक के सिगनलों को विच्छेदित (इन विनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप के सिवाए) नहीं करेगा।

प्रसारकों तथा डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों के बीच करार करने के लिए समय-सीमा

13.2क.7 (1) प्रत्येक प्रसारक, डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक से अंतरसंयोजन करार करने के लिए अथवा पहले ही किए गए अंतरसंयोजन करार में परिवर्धन के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, इन विनियमों के अधीन प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप करार करेगा अथवा ऐसे प्रचालक के साथ पहले ही किए गए करार को परिवर्धित करेगा।

(2) यदि कोई प्रसारक विनियम 13.2 क.5 में निर्दिष्ट किसी परिवर्धन की सूचना देता है, तो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट करार डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक के विकल्प पर उसी रीति से परिवर्धित होगा, जैसी कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत करार करने के समय थी।

13.2क.8 यदि प्रसारक तथा डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक अंतरसंयोजन करार करने में असफल रहते हैं, तो दोनों पक्ष संयुक्त रूप से, अधिनियम की धारा 14क के उपबंधों के साथ पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी भी समय, प्राधिकरण से अंतरसंयोजन करार करने के लिए प्रक्रिया को सुकर बनाने का अनुरोध कर सकेंगे।

13.2क.9 खंड 13.2 क.8 में अंतर्निहित किसी भी बात का आशय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत प्रसारक और डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को प्रदत्त किसी भी विधिक अधिकार को वापस लेना नहीं लगाया जाएगा तथा उनमें से कोई भी पक्ष, सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान, किसी भी समय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

13.2क.10 खंड 13.2 क.8 अथवा 13.2 क.9 में अंतर्निहित कोई भी बात ऐसे मामले अथवा मुद्दे पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में —

(क) अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित हो; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, कोई डिक्री, पंचाट अथवा कोई आदेश पारित किया गया हो।

अला-कार्टे आधार पर चैनलों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना

13.2क.11 प्रसारक के लिए डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को अला-कार्टे आधार पर पे-चैनल प्रदान करना अनिवार्य होगा तथा अला-कार्टे आधार पर चैनलों के इस प्रकार से प्रदान करने की प्रक्रिया प्रसारक को बुके के रूप में ऐसे पे-चैनल अतिरिक्त रूप से प्रदान करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह कि कोई भी प्रसारक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को वे समस्त बुके अथवा अन्य बुके प्रदान करने के लिए विवश नहीं करेगा जो ऐसे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक द्वारा इसके डीटीएच सब्सक्राइबर्स को प्रदान किए जा रहे किसी पैकेज अथवा स्कीम के तहत प्रसारक द्वारा ऐसे प्रचालक को प्रदान किए जा रहे हैं।

13.2क.12 अला-कार्टे आधार पर पे-चैनलों के लिए दरें तथा बुके के लिए दरें निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी; अर्थात्:—

(क) ऐसे बुके का भाग बना रहे पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों का योग किसी भी दशा में उस बुके की दर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसका कि पे-चैनल एक भाग है, तथा

(ख) ऐसे बुके का भाग बना रहे प्रत्येक पे-चैनल की अला-कार्टे दरें, किसी भी दशा में, उस बुके के पे-चैनल की औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी, जिसका का ऐसा पे-चैनल एक भाग है तथा बुके के पे-चैनल की औसत दर का आकलन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

यदि बुके दर रु0 'एक्स' प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर है, और बुके में पे-चैनलों की संख्या 'वाई' है, तो बुके की औसत प्रति चैनल दर रु0 'एक्स' भाग पे-चैनलों की संख्या 'वाई'

होगी।

13.2क.13 प्रत्येक डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी प्रसारक द्वारा प्रदान किए गए एक बुके अथवा अधिक बुके (जिसे इसके पश्चात् चुनिंदा बुके कहा गया है) का विकल्प लेता है, ऐसे बुके अथवा अधिक बुकों में से चैनलों की पैकेजिंग का निर्णय ले सकेगा, जोकि उसके द्वारा उसके डीटीएच सब्सक्राइबरों को प्रदान किए जा सकते हैं।

परंतु यह कि ऐसे मामले में जहां कोई डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक -

(क) अपने डीटीएच सब्सक्राइबरों को ऐसा बुके समस्त रूप से प्रदान नहीं करता है परंतु

ऐसे सब्सक्राइबरों को ऐसे चुनिंदा बुके में निहित केवल कुछ ही चैनल प्रदान करता है;

अथवा

(ख) ऐसे चुनिंदा बुके में निहित चैनलों के ऐसी रीति से पैकेज बनाता है कि ऐसे चुनिंदा

बुके में निहित विभिन्न चैनलों के लिए सब्सक्राइबर बेस भिन्न हो जाता है,

तो डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक द्वारा ऐसे समस्त चुनिंदा बुके के लिए भुगतान का आकलन उन चैनलों के लिए सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा जिनका कि उस बुके में निहित चैनलों में उच्चतम सब्सक्राइबर बेस है।

(ग) उप-विनियम 13.3 में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"13.3 यदि प्राधिकरण की यह राय है कि प्रसारण क्षेत्र और केबल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं या उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा के लिए अथवा प्रसारण क्षेत्र और केबल क्षेत्र के संवर्धन अथवा उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में परिवर्धन किए जाने की आवश्यकता है, अथवा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, तो यह, संबंधित प्रसारक को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करने के बाद, संबंधित प्रसारक से उक्त प्रस्ताव को परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा प्रसारक ऐसे परिवर्धन करेगा और परिवर्धनों के लिए अपेक्षा प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे परिवर्धनों को शामिल करने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव को प्रकाशित करेगा।"

आर. एन. चौबे, प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)

टिप्पणी 1. प्रधान विनियम अधिसूचना सं० 8-26/2004-बीएंडसीएस दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं० 3-57/2005-बीएंडसीएस दिनांक 3 मार्च, 2005, सं० 11-13/2006-बीएंडसीएस दिनांक 24 अगस्त, 2006 और सं० 6-4/2006-बीएंडसीएस दिनांक 4 सितम्बर, 2006, द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. पृष्ठभूमि

1. डायरेक्ट-टु-होम (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीटीएच सेवा कहा गया है) सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल अत्यंत उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से डिजिटल रूप में संपीडित, इंक्रीप्ट तथा विकीर्णित होते हैं। डीटीएच के माध्यम से संप्रेषित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटीना स्थापित कर सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि एक वैयक्तिक प्रयोक्ता सीधे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीटीएच प्रचालक कहा गया है) से सेवा प्राप्त करता है, अतः डीटीएच सेवा के संप्रेषण को किसी वाणिज्यिक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, मल्टीप्लेक्सड सिग्नलों को प्राप्त करने और उन्हें टेलीविजन सेट पर देखने के लिए एक डिजिटल रिसीवर, जिसे सामान्यतया सेट टॉप बॉक्स कहा जाता है, की आवश्यकता होती है।

2. भारत में, केबल ट्रांसमिशन की तुलना में डीटीएच सेवा का अभ्युदय हाल ही में हुआ है। डीटीएच एक एड्रेसेबल प्रणाली है तथा समस्त देश को कवर कर सकती है। डीटीएच लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के पास निहित है। एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को छोड़कर, दो डीटीएच प्रचालकों ने भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने प्रचालन शुरू किए हैं। ये हैं—मैसर्स एससी इंटरप्राइजेज (जोकि डिश टीवी के ब्रांड नाम से ज्ञात है) तथा मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड। डिश टीवी ने अक्टूबर, 2003 माह में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं तथा टाटा स्काई ने अपनी सेवा अगस्त, 2006 में आरंभ की थी। दोनों डीटीएच प्रचालक फ्री-टु-एयर चैनलों के साथ अनेक पे-चैनल प्रदान करते हैं तथा देश में उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या वर्तमान में लगभग 3.2 मिलियन होने का अनुमान है। इसकी तुलना में, अन्य एड्रेसेबल वितरण प्लेटफार्म, नामतः केबल टेलीविजन के लिए सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) के देश के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में

लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा (जिसे डीडी डायरेक्ट कहा जाता है) पर फ्री-टु-एयर चैनल उपलब्ध कराता है, जिसके लिए सब्सक्राइबर को खुले बाजार से डिश तथा सेट टॉप बॉक्स खरीदना पड़ता है। चूंकि दूरदर्शन सिगनल अन-इंक्रिप्टेड तथा फ्री-टु-एयर हैं, इसके दर्शकों की संख्या का सटीक आकलन उपलब्ध नहीं है। हाल ही में, मैसर्स सन टीवी लिमिटेड तथा मैसर्स रिलाएंस ब्लू मैजिक लिमिटेड को डीटीएच लाइसेंस दिए गए हैं तथा दो और संभावित डीटीएच प्रचालक लाइसेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

3. जैसाकि परामर्श-पत्र में उल्लेख किया गया है, डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की उपलब्धता हाल तक काफी सीमित थी। इस प्रकार, हालांकि डीटीएच सेवाएं देश में उपलब्ध थीं, ये केवल सेवाओं को कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा प्रदान नहीं कर रही थीं। डीटीएच प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय कंटेंट की उपलब्धता के साथ ही पिछले एक वर्ष में स्थिति में परिवर्तन आया है। पे-टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए डीटीएच तथा केबल टीवी के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि दो प्लेटफॉर्मों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के मुद्दे की जांच की जाए।

4. 31 दिसम्बर, 2006 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों में अधिसूचित क्षेत्रों में सर्जित उपागम प्रणाली (कैस) के क्रियान्वयन के साथ, केबल टेलीविजन सेवाओं के वितरण में एड्रसेबिलिटी चेन्नई से भी आगे विस्तारित कर दी गई है, जहां कैस 2003 में लागू किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में कैस का क्रियान्वयन कैस के लिए विनियामक ढांचे को लागू करने से पूर्व किया गया था। कैस के लिए विनियामक ढांचे में मुख्य रूप से कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अंतरसंयोजन विनियम में संशोधनों के माध्यम से निर्दिष्ट मानक अंतरसंयोजन करार तथा कैस क्षेत्रों में बुनियादी सेवा टियर प्रभारों की कीमतों, पे-चैनलों के प्रभारों पर सीमा तथा सेट टॉप

बॉक्स के लिए मानक टैरिफ प्लानों को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक आदेश शामिल था। तदनुसार, डीटीएच सेवाओं हेतु समान विनियामक ढांचे के लिए सब्सक्राइबर्स तथा कुछ सेवा प्रदाताओं से मांगें उठी हैं।

5. डीटीएच सेवा प्रदाता इस बात के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं कि कुछ प्रसारकों के साथ उनके करार उन्हें अलोकप्रिय कंटेंट करी कराने के लिए बाध्य करते हैं और यह कि इसके परिणामस्वरूप सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रसार उच्च हो जाते हैं। डीटीएच प्रसारकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि किसी मानक करार तथा प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र के अभाव में उन्हें उपभोक्ता हित में प्रसारकों के साथ ऐसे खंडों वाले करारों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। डीटीएच सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। एक डीटीएच प्रचालक ने प्राधिकरण से डीटीएच वितरण के लिए एक "मानक अंशदायी करार" तैयार करने का अनुरोध भी किया है, जो सभी प्रसारकों पर समान रूप से लागू हो।

6. कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे में, जोकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में कैस के क्रियान्वयन के संक्षेप पर निर्धारित किया गया था, मानक अंतरसंयोजन करार शामिल थे, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को अंतरसंयोजन विनियमों में संशोधन द्वारा निर्दिष्ट किए गए थे। कैस क्षेत्रों से बाहर केबल सेवाओं (नॉन-एड्रसेबल मोड में) के संबंध में दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अंतरसंयोजन विनियम दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को संशोधित किए गए थे, जिनमें प्रसारकों को अब उनके सदस्य अंतरसंयोजन प्रस्तावों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तदनुसार, विद्यमान डीटीएच प्रचालकों तथा संभावित प्रचालकों से डीटीएच सेवाओं हेतु एक प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र के लिए मांगें उठ रही हैं ताकि युक्तिसंगत प्रसिद्धियों और कंटेंट की

उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

डीटीएच सेवाओं के लिए मानक टैरिफ प्लानों को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक आदेश शामिल था। तदनुसार, डीटीएच सेवाओं हेतु समान विनियामक ढांचे के लिए सब्सक्राइबर्स तथा कुछ सेवा प्रदाताओं से मांगें उठी हैं।

डीटीएच सेवाओं के लिए मानक टैरिफ प्लानों को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक आदेश शामिल था। तदनुसार, डीटीएच सेवाओं हेतु समान विनियामक ढांचे के लिए सब्सक्राइबर्स तथा कुछ सेवा प्रदाताओं से मांगें उठी हैं।

डीटीएच सेवाओं के लिए मानक टैरिफ प्लानों को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक आदेश शामिल था। तदनुसार, डीटीएच सेवाओं हेतु समान विनियामक ढांचे के लिए सब्सक्राइबर्स तथा कुछ सेवा प्रदाताओं से मांगें उठी हैं।

ख. परामर्श-प्रक्रिया

7. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ट्राई अधिनियम, 1997 कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) और (iii) प्राधिकरण के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोज्यता के निबंधन और शर्तें निर्धारित करने तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने का उपबंध करते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (4) प्राधिकरण से इसके अधिकारों का प्रयोग करने तथा इसके कृत्यों का निर्वहन करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीटीएच सेवाओं के लिए एक प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र उपलब्ध कराने से पूर्व परामर्श-प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया।

8. परामर्श प्रक्रिया डीटीएच से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 2 मार्च, 2007 को परामर्श-पत्र जारी करने के माध्यम से प्रारंभ हुई थी जिसमें पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। 27 पणधारकों/प्रतिनिधियों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। परामर्श-पत्र पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर पणधारकों के प्रतिनिधियों के साथ आगे विचार-विमर्श के लिए भुवनेश्वर में 18 मई, 2007 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी।

ग. परामर्श के लिए मुद्दे

9. परामर्श-पत्र में परामर्श के लिए जो मुद्दे उठाए गए थे वे निम्नानुसार हैं:-

- (i) क्या प्रसारकों तथा डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित किया जाना चाहिए?
- (ii) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण को प्रसारकों द्वारा डीटीएच प्लेटफार्मों को कंटेंट के प्रावधान के लिए "मानक अंतरसंयोजन करार" तैयार तथा अधिदेशित करने चाहिए अथवा

इस प्रयोजन के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) पद्धति अपनाई जानी चाहिए?

(iii) क्या कोई अन्य पद्धति है जिसके द्वारा इन व्यवस्थाओं को विनियमित किया जा सके?

10. परामर्श-पत्र में लाइसेंस करार में "मस्ट कैरी" प्रावधान तथा डीटीएच सेवाओं के लिए कैरिज शुल्क के विनियम के बारे में निम्नलिखित मुद्दे भी उठाए गए थे:-

(i) क्या विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर एक्सेस का प्रावधान की अपेक्षा करने वाले खंड को समाप्त करने के लिए डीटीएच लाइसेंस शर्तों को संशोधित किया जाना चाहिए?

(ii) विकल्पतः, क्या व्यवस्थापन अंश के आधार पर केवल लोकप्रिय कंटेंट का कैरिज अधिदेशित किया जाना चाहिए, जैसाकि स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों द्वारा अवधारित किया गया है?

(iii) क्या डीटीएच प्लेटफार्मों के लिए कैरिज शुल्क विनियमित किया जाना चाहिए? यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया जाएगा?

घ. परामर्श-प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

11. परामर्श-प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की गई है तथा उपयुक्त बुनियादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जबकि सभी पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया है, यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों में, सब्सक्राइबर, डीटीएच प्रचालक तथा प्रसारक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्ष होते हैं। अन्य पणधारक जैसे, केबल प्रचालक तथा मल्टी सिस्टम

प्रचालक डीटीएच सेवाओं के लिए अंतरसंयोजन ढांचे द्वारा सीधे प्रभावित नहीं हैं। परामर्श-प्रक्रिया के दौरान पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिया गया है। पश्चातवर्ती पैराग्राफ विभिन्न पणधारकों से प्राप्त मुद्दावार टिप्पणियों को संक्षेप में कवर करते हैं तथा विनियम के लिए आधार तथा तर्काधार निर्धारित करते हैं।

घ.1 डीटीएच के लिए अंतरसंयोजन करार

12. जबकि विद्यमान तथा संभावित डीटीएच प्रचालकों से प्राप्त टिप्पणियां प्रत्याशित थीं, जिनमें सभी ने अपेक्षित विनियामक ढांचे के रूप में मानक अंतरसंयोजन करारों का सुझाव दिया था, इस मुद्दे पर प्रसारकों में मतभेद था। अधिकांश प्रसारक अंतरसंयोजन करारों के लिए किसी विनियम के पक्ष में नहीं थे। एक प्रसारक ने मानक अंतरसंयोजन करार पद्धति का समर्थन किया तथा दूसरे ने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव मार्ग की अनुशंसा की। उपभोक्ता संगठनों तथा व्यक्ति-विशेषों का यह मत था कि मानक अंतरसंयोजन करारों के माध्यम से प्रसारकों तथा डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। केवल प्रचालकों ने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का समर्थन किया।

घ.2 मस्ट कैरी / कैरिज शुल्क

13. अधिकांश विद्यमान तथा संभावित डीटीएच प्रचालकों का यह मत था कि गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले खंड को बनाए रखा जाना चाहिए। कतिपय बड़े प्रसारकों ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की। तथापि, कतिपय छोटे प्रसारक एक डीटीएच ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक प्रसारक को कम-से-कम पांच चैनलों का आवंटन चाहते थे। इसे समझा जा सकता है क्योंकि पांच चैनलों से कम की धारिता वाले किसी प्रसारक के लिए ऐसा कोई सूत्रीकरण स्वतः ही 'मस्ट कैरी' समाविष्ट कर देता है, जो गैर-भेदभाव आधार पर विभिन्न कंटेंट

प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले वर्तमान खंड के मामले में नहीं है। केबल ऑपरेटरों, एक एमएसओ और एक भावी डीटीएच ऑपरेटर ने गैर-भेदभाव आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले खंड को हटाने के पक्ष में राय दी है।

14. जहां तक कैरिज शुल्क को विनियमित करने का संबंध है, इस बात पर लगभग सहमति थी कि इसे बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथापि, एक संभावित डीटीएच ऑपरेटर ने कैरिज शुल्क की राशि पर सीमा लगाने की सिफारिश की। एक छोटे प्रसारक और केबल ऑपरेटरों के एक संघ ने भी कैरिज शुल्क को विनियमित किए जाने की इच्छा जताई।

ड दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में संशोधन करने के लिए तर्काधार

15. प्राधिकरण ने यह तथ्य नोट किया कि दो विद्यमान डीटीएच ऑपरेटर कुछ प्रसारकों से उनके डीटीएच प्लेटफार्मों के लिए लोकप्रिय कंटेंट की एक्सेस प्राप्त करने के लिए माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के पास गए जबकि अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 में स्पष्टतः निर्धारित किया गया है कि "प्रत्येक प्रसारक, अनुरोध करने पर, टीवी चैनलों के सभी वितरकों को गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों पर इसके टीवी चैनलों के सिगनल प्रदान करेगा, जिसमें शामिल होंगे परंतु सीमित नहीं होंगे, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हेड्स एंड इन द स्काई ऑपरेटर।" वर्तमान परिदृश्य में, जहां निकट भविष्य में और अधिक प्लेयरों द्वारा अपने डीटीएच प्लेटफार्म शुरू किए जाने की संभावना है, एक विनियामक ढांचे का होना आवश्यक होगा, जो वर्तमान तथा नए डीटीएच ऑपरेटरों को उनकी पसंद के कंटेंट की एक्सेस प्राप्त करने को सुकर बनाए और यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं डीटीएच पर अपनी पसंद के चैनल देख सकें।

16. एक सौम्य विनियम तैयार करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन करारों को विनियमित करने के तरीके के रूप में मानक अंतरसंयोजन करारों पर संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को प्राथमिकता दी है। यह कार्यप्रणाली, प्रसारक को उसके कारोबार और बाजार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसके विनियमों/निर्देशों में निर्णित किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के अधीन उनके 'संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को तैयार करने का विकल्प प्रदान करती है। इसके साथ-साथ प्राधिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी हस्तक्षेप की शक्ति को अपने पास उस स्थिति के लिए सुरक्षित रखे जब उपभोक्ताओं या सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा की जानी हो, या जब एक आरआईओ अंतरसंयोजन विनियम के अनुरूप न हो या जब क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाना है। तदनुसार, प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित करने के लिए विनियमों में आरआईओ कार्यप्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

17. गैर-एड्रसेबल प्रणाली (गैर-कैस क्षेत्रों में) के माध्यम से वितरित की जा रही केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए आरआईओ कार्य प्रणाली का प्रयोग प्रचलन में है। तथापि, डीटीएच प्लेटफार्म भी एड्रसेबल हैं और यह सब्सक्राइबर आधार के बारे में किसी अस्पष्टता को दूर करेगी। इसके अतिरिक्त, यदि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में अधिकांश महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें शामिल होती हैं, तो किसी अंतरसंयोजन करार पर न पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस उद्देश्य से, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 में शामिल किया गया है। ऐसी निबंधन और शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, चैनलों की दरों और छूटों, भुगतान संबंधी शर्तों, सुरक्षा और पायरेसी-रोधी अपेक्षाओं, सब्सक्राइबर की रिपोर्टों और लेखापरीक्षा, करार की अवधि और करार की समाप्ति आदि से संबंधित हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में मुख्य वित्तीय निबंधन और शर्तों (दर, छूट, भुगतान संबंधी शर्तें और सब्सक्राइबर

आधार) को शामिल किया जाए जिन्हें डीटीएच सेवाओं में सभी पणधारकों के हितों की रक्षा के लिए उपबंध बनाते समय बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया गया है। सुरक्षा और पायरेसी-रोधी उपायों के अन्य विवादित मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अतः संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों से अंतरसंयोजन करारों पर पहुँचने में बिलंब में कमी होने की संभावना है।

18. चूँकि प्रसारकों से अंतरसंयोजन की मांग करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या सीमित है (इस समय केवल दो), यह अधिदेशित किया गया है कि प्रसारक, अपने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों के बारे में सभी डीटीएच ऑपरेटरों को सूचित करेंगे। चूँकि डीटीएच ऑपरेटरों को लाइसेंस देना एक सतत प्रक्रिया है, नए डीटीएच ऑपरेटरों के पास संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों के लिए अनुरोध करने का अधिकार है और प्रसारकों द्वारा उन्हें उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ-साथ, एक्सेस और तत्काल संदर्भ को सरल बनाने के प्रयोजनार्थ, प्रसारकों की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों को प्रकाशित करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी प्रकार, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों में किए गए किसी परिवर्तन की जानकारी डीटीएच ऑपरेटरों को देना और उसे वेबसाइट पर प्रकाशित करना भी अपेक्षित है। डीटीएच ऑपरेटरों को भी वर्तमान अंतरसंयोजन करारों में परिवर्धन करने का विकल्प दिया गया है ताकि वह इन विनियमों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप रहे।

19. अंतरसंयोजन करार पर पहुँचने के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव ही मात्र एक कार्यप्रणाली है और सेवा प्रदाता तथा प्रसारक पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर अंतरसंयोजन करार कर सकते हैं। तथापि, चूँकि अध्यारोही सिद्धान्त गैर-भेदभावपूर्ण आधार के सिगनलों का प्रावधान है, प्रसारक को किसी अन्य डीटीएच ऑपरेटर को भी समान निबंधन और शर्तों की पेशकश करनी अपेक्षित होगी, यदि उस अन्य डीटीएच ऑपरेटर द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है।

इसके साथ-साथ, गैर-भेदभावपूर्ण एक्सेस के सिद्धान्त में यह निहित है कि जिन डीटीएच ऑपरेटरों ने प्रसारकों के साथ अंतरसंयोजन करारों पर पहले ही हस्ताक्षर किए हुए हैं, उन्हें भी प्रसारक द्वारा यथाप्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर नए अंतरसंयोजन करार करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।

20. कंटेंट की एक्सेस के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव कार्यप्रणाली को एक प्रभावी साधन बनाने के लिए एक ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है जिसके भीतर प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर के साथ संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर अंतरसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करे। तदनुसार, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 में 45 दिनों की एक समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है।

21. ऐसी स्थिति, जिसमें दोनों पक्ष अर्थात् प्रसारक और डीटीएच ऑपरेटर संयुक्त रूप से प्राधिकरण के पास जाएं और प्राधिकरण से कोई अंतरसंयोजन करार करने में सहायता करने का अनुरोध करें, से संबंधित प्रावधान, प्राधिकरण द्वारा 7 जून, 2007 को जारी केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधा हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 में दिए गए समान प्रावधानों पर आधारित हैं। ये प्रावधान, मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा केवल किसी अंतरसंयोजन करार को समर्थ बनाने के लिए हैं। ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत दोनों पक्षों को अन्यथा प्राप्त कानूनी अधिकारों और उपचार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं।

22. डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि प्राधिकरण एक साथ बंडल किए गए सभी चैनलों, जो उनकी राय में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं, को कैरी करने की बाध्यता के बिना कंटेंट की एक्सेस को सरल बनाए। डीटीएच सेवाओं के टैरिफ में वृद्धि से संबंधित एक शिकायत पर भी, एक डीटीएच सेवा प्रदाता ने चैनलों की बंडलिंग

को उच्च टैरिफ का एक कारण माना है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह महसूस करना आवश्यक समझा गया कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में चैनलों के अला-कार्टे मूल्यों की घोषणा आदेशित की जानी चाहिए। अला-कार्टे आधार पर चैनलों के प्रावधान को आदेशित किए बिना, वर्तमान अंतरसंयोजन विनियम में संशोधन का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

23. गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न विषय प्रदाताओं/चैनलों को एक्सेस देने की अपेक्षा करने वाली डीटीएच लाइसेंस करार की निबंधन और शर्तों के खंड 7.6 पर चर्चा करते हुए, माननीय टीडीएसएटी ने टाटा स्काई लिमिटेड बनाम जी टर्नर लिमिटेड और अन्य के मामले में 2006 की याचिका सं० 189 (सी) के संबंध में 31 मार्च, 2007 के अपने आदेश में यह कहा था कि:-

".....यदि कोई डीटीएच ऑपरेटर को प्रत्येक प्रसारक के सभी चैनल लेने हों, तो ऐसा करना वास्तविक रूप में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्येक चैनल को लिया जाना है, तो इसका यह अर्थ है कि उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। इससे डीटीएच ऑपरेटर की लागत बढ़ जाएगी। अतः इस लागत का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। यदि डीटीएच, खर्चीला बन जाता है तो उपभोक्त उससे दूर भागेंगे। यह कैसे या केबल के साथ मुकाबला करने में समर्थ नहीं होगा। अतः खंड 7.6 की ऐसी कोई परिभाषा उपभोक्ता विरोधी हो सकती है"

24. सब्सक्राइबर्स के लिए डायरेक्ट-टु-होम सेवाओं की लागत में वृद्धि के अलावा, डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों हेतु चैनलों की अला-कार्टे उपलब्धता अधिदेशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कारण है। उन चैनलों की संख्या पर तकनीकी सीमा है जो एक डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक अपने प्लेटफार्म पर करी करता है। वर्तमान में, देश में अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग के अंतर्गत 27 चैनलों की अनुमति है। किसी उपग्रह पर ट्रांसपोंडर क्षमता सीमित है तथा एक डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक प्रयुक्त संपीड़न प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए प्रति ट्रांसपोंडर लगभग 12 चैनल बीम कर सकता है। ट्रांसपोंडर

स्थान की उपलब्धता डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए चैनलों की संख्या को सीमित करेगी। इंसैट 4ए और इंसैट 4बी की 12 केयू बैंड तथा 12 सी बैंड प्रति ट्रांसपोंडर क्षमता है। अतः एक इंसैट उपग्रह का प्रयोग कर रहे डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक के लिए सभी 270 चैनल प्रदान करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। माननीय टीडीसैट ने टाटा स्काई बनाम जी टर्नर लिमिटेड और अन्य के मामले में 2006 की याचिका सं० 189 में 31 मार्च, 2007 के अपने आदेश में कहा है कि:-

".....यह प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है कि कोई डीटीएच प्रचालक किसी विशेष प्रसारक के सभी चैनल नहीं लेना चाहेगा और अवांछित चैनल लेकर अपनी ट्रांसपोंडर क्षमता को समाप्त नहीं करना चाहेगा। क्योंकि डीटीएच प्रदाता कारोबार कर रहा है और उसे अपने कारोबार के हित को देखना है"

25. तथापि, अला-कार्टे आधार पर चैनलों के प्रावधान ने भी अला-कार्टे आधार पर चैनलों की कीमत और बुके की कीमत के बीच संबंध को विनियमित करने की आवश्यकता को जरूरी माना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चैनलों की अला-कार्टे पसंद चैनलों और चैनलों के बुके के हानिकारक मूल्य-निर्धारण के कारण भ्रामक न बन जाए। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स हेतु अला-कार्टे और बुके मूल्यों के बीच सह-संबंध हेतु दिए गए फार्मूले को डीटीएच ऑपरेटरों के लिए भी अपनाया गया है।

26. डीटीएच ऑपरेटरों ने भी उनके द्वारा चुने हुए बुके के चैनलों को पैकेज करने के लिए स्वतंत्रता मांगी है। उन्होंने अपनी मांग को तर्कसंगत ठहराने के लिए कंटेंट की पैकेजिंग इस तरीके से करने की आवश्यकता बताई है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय रुचि के अनुसार कंटेंट को स्थानीय स्वरूप दे। प्राधिकरण ने इसे अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ, यह अधिदेशित करके प्रसारकों के हितों की रक्षा की गई है कि किसी बुके में किसी चैनल के लिए उच्च सब्सक्राइबर आधार प्रसारक को समस्त बुके के लिए भुगतान का आधार होगा।

27. गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा करने वाले डीटीएच लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों का खंड 7.6 डीटीएच लाइसेंसिंग प्रावधानों के निबंधन और शर्तों की व्याप्ति के भीतर है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) है। अतः उक्त खंड का संशोधन अंतरसंयोजन मुद्दों पर इस विनियम के अधिकारक्षेत्र से बाहर है। तदनुसार, इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस मुद्दे पर और आगे चर्चा नहीं की जा रही है।

28. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 बनाते समय प्राधिकरण ने विभिन्न पणधारकों अर्थात् प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और डायरेक्ट-टु-होम सब्सक्राइबर्स के हितों में संतुलन स्थापित करने तथा एक दूरसंचार सेवा होने के नाते डायरेक्ट-टु-होम सेवा में विकास को प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास किए हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2007.

The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007

(No. 9 of 2007)

F. No. 4-54/2007-B & CS.— In exercise of the powers conferred by section 36, and by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,-----

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub section (1) of section 2 of the said Act, and
(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary,

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004) namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007.

(2) They shall come into force on the 1st day of December, 2007.

2. In the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004, (hereinafter referred to as the principal regulation), in clause 2,-

(i) after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

‘(aa) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997);’

(ii) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

‘(ia) “commercial subscriber” means any subscriber who receives a programming service at a place indicated by him to a service provider and uses signals of such service for the benefit of his clients, customers, members or any other class or group of persons having access to such place;

(iii) in sub-clause (k), the words “in KU band” shall be omitted;

(iv) after sub-clause (k), the following sub-clauses shall be inserted, namely :-

‘(ka) “direct to home service” means distribution of multi channel TV programmes by using a satellite system by providing TV signals directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary such as cable operator or any other distributor of TV channels;

(kb) “direct to home subscriber” means a subscriber who receives the signals of a direct to home service;’

(v) after sub-clause (m), the following sub-clauses shall be inserted, namely :-

(ma) “ordinary subscriber” means any subscriber who receives a programming service from a service provider and uses the same for his domestic purposes;’

‘(mb) “pay channel” means a channel for which fees is to be paid to the broadcaster by the person receiving the signals from the broadcaster, for its re-transmission through electromagnetic waves through cable or through space intended to be received by the general public either directly or indirectly;

(mc) “programme” means any television broadcast and includes-

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials through video cassette recorders or video cassette players;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation, and the expression ‘programming service’ shall be construed accordingly;

(vi) after sub-clause (n), the following sub-clause shall be inserted namely :-

‘(na) “subscriber” means a person who receives the signals of a service provider at a place indicated to the service provider by him without further transmitting it to any other person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers unless specifically excluded;’

3. In regulation 13 of the principal regulation,---

(a) in sub-regulation 13.1, in the opening portion beginning with the figures and words "13.1. All broadcasters shall submit.....", the following shall be substituted, namely:-

"Reference Interconnect Offers for non-addressable systems.

13.1 All broadcasters shall submit----";

(b) after sub-regulation 13.2, the following shall be inserted, namely:-

"13.2A Reference Interconnect Offers for direct to home service.

13.2A.1 Every broadcaster, providing broadcasting services before the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007) and continues to provide such services after such commencement shall, within ninety days from the date of such commencement, intimate to all the direct to home operators existing on that date and coming into existence within the said period of ninety days, its Reference Interconnect Offer specifying, *inter-alia*, the technical and commercial terms and conditions for interconnection for the direct to home platform, including the following terms and conditions, namely:-

- (a) rates of the channels on a-la-carte basis and the rates of bouquets offered by the broadcaster to the direct to home operator;
- (b) details of discounts, if any;
- (c) payment terms;
- (d) security and anti-piracy requirements;
- (e) subscriber reports based on subscriber management system and audit;
- (f) tenure of agreement;
- (g) termination of agreements.

13.2A.2 Every broadcaster shall publish a copy of the Reference Interconnect Offer, referred to in sub regulation 13.2A.1, on its website:

Provided that any broadcaster, who had intimated or published on its website, before the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), any Reference Interconnect Offer, shall modify such Reference Interconnect Offer so as to be in conformity with the Reference Interconnect offer referred to in regulation 13.2A.1 and publish the same as required under this sub-regulation.

13.2A.3 Every broadcaster, who begins to provide broadcasting services after the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007) shall, within ninety days of such commencement or before providing such services, whichever is later, intimate to all the direct to

home operators existing on that date, its Reference Interconnect Offer specifying therein the the technical and commercial terms and conditions referred to in sub-regulation 13.2A.1 and publish the same, before or simultaneously with such intimation, on its website.

13.2A.4 Every direct to home operator, who has been granted a licence after ninety days from the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), may request a broadcaster for being provided with a copy of Reference Interconnect Offer of such broadcaster and such broadcaster shall, within ten working days from the date of receipt of such a request, provide the same to the direct to home operator.

13.2A.5 Every broadcaster, who makes any modification to its Reference Interconnect Offer referred to in sub-regulation 13.2A.1 or sub-regulation 13.2A.3, shall, immediately after such modifications, intimate to all the direct to home operators such modifications so made to its Reference Interconnect Offer:

Provided that all such modifications shall be published and exhibited on its website in the same manner as the Reference Interconnect Offer had been intimated to the direct to home operators and published on the website of the broadcasters.

Agreements between the broadcasters and direct to home operators.

13.2A.6 (1) The Reference Interconnect Offer of a broadcaster referred to in clause 13.2A.1 or 13.2A.3 or 13.2A.5, as the case may be, and intimated to the direct to home operators and published by the broadcaster on its website shall be the basis for all interconnection agreements to be entered into between the broadcaster and direct to home operators:

Provided that the broadcaster may enter, on non discriminatory basis, into agreements with different direct to home operators modifying the Reference Interconnect Offer on such terms and conditions as may be agreed upon between them :

Provided further that in case a broadcaster had entered, before the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), into an agreement with any direct to home operator and publishes, subsequently, its Reference Interconnect Offer (including its modifications) under said regulations, such broadcaster shall, after publication of the said offer, give an option to such direct to home operator to either enter into an agreement in accordance with these regulations or continue with the agreement entered before such commencement till its validity.

(2) No broadcaster, who had, before the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), entered into an agreement with a direct to home operator and such direct to home operator has given an option under sub-regulation (1), to enter into an agreement with such broadcaster in accordance with the Reference Interconnect Offer published after such commencement, shall disconnect signals (except in accordance with these regulations or any other law for the time being in force) during the period beginning from the date on which such operator gave the option and ending on the date on which such agreement was entered in accordance with the Reference Interconnect Offer or the date of expiry of earlier agreement, whichever was earlier.

(3) No broadcaster, who had, before the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), entered into an agreement with a direct to home operator and such direct to home operator has given an option under sub-regulation (1), to continue with the agreement entered, before such commencement, with such broadcaster, shall disconnect signals of such operator (except in accordance with these regulations or any other law for the time being in force) during the validity of such agreement.

Time limit for entering into agreements between the broadcasters and direct to home operators.

13.2A.7 (1) Every broadcaster shall, within a period of forty-five days from the date of receipt of request from a direct to home operator for entering into interconnection agreement or for modification of an interconnection agreement already entered, shall enter into an agreement, or, modify such agreement already entered, with such direct to home operator, in accordance with the Reference Interconnect Offer published under these regulations.

(2) In case a broadcaster intimates any modification as referred to in regulation 13.2A.5, the agreement referred to in sub-regulation (1) shall be modified at the option of the direct to home operator, in the same manner as that of entering into of an agreement under sub-regulation (1).

13.2A.8 In case the broadcaster and the direct to home operator fail to enter into an interconnection agreement, then both of them may jointly, without prejudice to the provisions of section 14A of the Act, at any time, request the Authority to facilitate in the process for entering into an interconnection agreement.

13.2A.9 Nothing contained in clause 13.2A.8 shall be construed to take away any legal right conferred upon the broadcaster and the direct to home operator under any law for the time being in force and either of them may, at any time during the facilitation process, exercise such right conferred upon them under any law for the time being in force.

13.2A.10 Nothing contained in clause 13.2A.8 or 13.2A.9 shall apply to any matter or issue for which ---

- (a) any proceedings are pending before any court or tribunal under the Act or any other law for the time being in force; or
- (b) a decree, award or an order has already been passed by any competent court or tribunal or Authority, as the case may be.

Compulsory offering of channels on a-la-carte basis.

13.2A.11 It shall be mandatory on the part of the broadcasters to offer pay channels on a-la-carte basis to direct to home operators and such offering of channels on a-la-carte basis shall not prevent the broadcaster from offering such pay channels additionally in the form of bouquets:

Provided that no broadcaster shall, directly or indirectly, compel any direct to home operator to offer the entire bouquet or bouquets offered by the broadcaster to such operator in any package or scheme being offered by such direct to home operator to its direct to home subscribers.

13.2A.12 The rates for pay channels on a-la-carte basis and rates for bouquets shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) The sum of the a-la-carte rates of the pay channels forming part of such a bouquet shall in no case exceed one and half times of the rate of that bouquet of which such pay channels are a part; and
- (b) the a-la-carte rates of each pay channel, forming part of such a bouquet, shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of that bouquet of which such pay channel is a part and the average rate of a pay channel of the bouquet be calculated in the following manner, namely:- If the bouquet rate is Rs. 'X' per month per subscriber and the number of pay channels is 'Y' in a bouquet, then the average pay channel rate of the bouquet shall be Rs. 'X' divided by number of pay channels 'Y'.

13.2A.13 Every direct to home operator, who, after the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007), opts for one bouquet or more bouquets (hereafter referred to as the opted bouquet) offered by a broadcaster, may decide the packaging of the channels from such bouquet

or bouquets which may be offered by it to its direct to home subscribers:

Provided that in a case where a direct to home operator--

(a) does not offer such opted bouquet as a whole to its direct to home subscribers but offers to such subscribers only certain channels comprised in such opted bouquet; or

(b) packages the channels comprised in such opted bouquet in a manner resulting in different subscriber base for different channels comprised in such opted bouquet,

then, the payment, to the broadcaster for such entire opted bouquet by the direct to home operator, shall be calculated on the basis of the subscriber base for the channel which has the highest subscriber base amongst the channels comprised in that bouquet.”.

(c) for sub regulation 13.3 the following . sub-regulation shall be substituted, namely

“13.3 In case the Authority is of the opinion that the Reference Interconnect Offer requires modifications so as to protect the interests of service providers or consumers of the broadcasting sector and cable sector, or to promote or ensure orderly growth of the broadcasting sector and cable sector or the Reference Interconnect Offer has not been prepared in accordance with the provisions of these regulations, it may, after giving an opportunity of being heard to the concerned broadcaster, require the concerned broadcaster to modify the said offer and such broadcaster shall make such modifications and publish, within fifteen days of receipt of requirement for the modifications, the said offer after incorporating such modifications.”.

R. N. CHOUBEY, Principal Advisor (B & CS)

Note 1.-----The principal regulations were published vide notification no. 8-26/2004-B&CS dated 10th December, 2004 and subsequently amended vide notifications no.3-57/2005-B&CS dated 3rd March, 2005, no.11-13/2006-B&CS dated 24th August, 2006 and no. 6-4/2006-B&CS dated 4th September, 2006.

Note 2.-----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007.

Annex

EXPLANATORY MEMORANDUM**A. Background**

1. In a direct to home service (hereinafter referred to as DTH service), a large number of television channels are digitally compressed, encrypted and beamed from very high power satellites. The programmes transmitted through DTH can be directly received at homes by installing small dish antennas at convenient locations in the buildings. DTH service transmission does not require any commercial intermediary, since an individual user is directly served by the direct to home operator (hereinafter referred to as DTH operator). However, a digital receiver usually referred to as set top box is required to receive the multiplexed signals and view them on a Television set.

2. In India, DTH service is a comparatively recent entrant as compared to cable transmission. DTH is an addressable system and can cover the entire country. The authority to issue DTH licence vests with the Government of India (Ministry of Information & Broadcasting). Leaving aside the Doordarshan as a public service broadcaster, two DTH operators have commenced their operations after obtaining licence from the Government of India (Ministry of Information & Broadcasting). These are M/s ASC Enterprises (under the brand name of Dish TV) and M/s Tata Sky Ltd. Dish TV had launched its services in the month of October 2003 and Tata Sky launched its service in the month of August 2006. The two DTH operators offer several pay channels along with Free to Air channels and the number of their subscribers in the country is estimated to be about 3.2 million at present. As compared to this, the other addressable delivery platform, namely, Conditional Access System (CAS) for cable television has about 5.5 lakh subscribers in the CAS notified areas of the country. The Doordarshan provides free to air channels on its DTH service (called DD Direct) for which the subscribers have to buy the dish and the set top box from the open market. Since the Doordarshan signals are unencrypted and free to air, no accurate assessment is available about the number of viewers. Recently, licences for DTH service have also been given to M/s. Sun TV Ltd. and M/s. Reliance Blue Magic Ltd, and two more potential DTH operators are awaiting the licence.

3. As pointed out in the consultation paper, availability of content on the DTH platform was limited till very recently. Hence, even though DTH services were available in the country, these were not offering any real competition to the cable services. The situation has changed in the last one year with the availability of popular content on the DTH platform. In view of the increasing competition between DTH and cable TV for providing pay TV services, it has become necessary to examine the issue of level playing field for the two platforms.

4. With the roll out of Conditional Access System (CAS) in the notified areas of the three metropolitan cities of Delhi, Mumbai and Kolkata on the 31st December, 2006, addressability in distribution of cable television services has been extended beyond Chennai, where CAS had been implemented in 2003. Roll out of CAS in the notified areas of the three metropolitan cities of Delhi, Mumbai and Kolkata was preceded by putting in place a regulatory framework for CAS by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority). The regulatory framework for CAS primarily consisted of Quality of Service Regulation for cable services in CAS areas. Standard Interconnection Agreements specified through an amendment to Interconnection Regulations dated the 10th December, 2004 and a Tariff order governing the prices of Basic Service Tier charges in CAS areas, ceiling on pay channel charges and standard tariff plans for set top boxes. Accordingly, there have been demands from the subscribers and some service providers for a similar regulatory framework for DTH service.

5. The DTH service providers have been representing that their agreements with some of the broadcasters force them to carry unpopular content also and that this leads to higher charges for all consumers. It has been pointed out by the DTH Operators that they had to sign the agreements with such clauses with the broadcasters in the consumer interest in the absence of any standard agreement and effective interconnect mechanism. The DTH service providers also requested the Authority to take action in the matter. One of the DTH operators has requested the Authority to formulate a "standard subscription agreement" for DTH distribution, which is uniformly applicable to all the broadcasters.

6. The regulatory framework for cable services in CAS areas, laid down at the time of roll out of CAS in notified areas of the three metropolitan cities of Delhi, Mumbai and Kolkata, included Standard Interconnection Agreements specified through an amendment to Interconnection Regulations dated the 10th December, 2004. In respect of cable services outside CAS areas (in non-addressable mode), the Interconnection Regulations dated the 10th December, 2004 were amended on the 4th September, 2006 whereby the broadcasters are now required to file their Reference Interconnect Offers. Accordingly, there have been demands from the existing DTH operators and potential operators for an effective interconnect mechanism for DTH services to ensure availability of content on reasonable terms.

B. Consultation Process

7. Sub-clauses (ii) & (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (hereinafter referred to as the TRAI Act, 1997), provide for the Authority to fix the terms and conditions of inter-connectivity between the service providers and to ensure technical compatibility and effective inter-connection between different service providers. Sub-section (4) of Section 11 of the TRAI Act, 1997 requires the Authority to ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions. Accordingly, the Authority decided to go in for a consultation process before providing for an effective interconnect mechanism for DTH services.

8. The process of consultation was initiated by circulating a consultation paper on the issues relating to DTH on the 2nd March, 2007 inviting inputs from the stakeholders. Responses were received from 27 stakeholders/representatives. An open house discussion was also held on the 18th May, 2007 in Bhubaneswar with representatives of stakeholders to further deliberate on various issues raised in the consultation paper.

C. Issues for Consultation

9. The issues which were raised for consultation in the consultation paper are as under:-

- (i) Should the interconnection agreements between broadcasters and DTH service providers be regulated?
- (ii) If yes, whether the Authority should formulate and mandate "Standard Interconnection Agreements" for provision of content by the broadcasters to DTH platforms or should the Reference Interconnect Offer (RIO) methodology be adopted for the purpose?
- (iii) Is there any other method by which these agreements should be regulated?

10. The consultation paper also posed following issues regarding "must carry" provisions in the licence agreement and regulation of carriage fee for DTH services:-

- (i) Should the DTH licence conditions be amended to do away with the clause requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis?
- (ii) Alternatively, whether carriage of only popular content should be mandated on the basis of viewer ship share as determined by independent monitoring agencies?
- (iii) Should the carriage fee for DTH platforms be regulated? If so, how should it be done?

D. Analysis of the responses received during the consultation process

11. The responses received during the consultation process have been examined and analyzed in detail in the background of the above basic approach. While comments received from all the stakeholders have been considered, it is important to remember that in issues relating to interconnection, the subscribers, the DTH operators and the broadcasters are the directly affected parties. Other stakeholders like cable operators and multi system operators are not directly affected by interconnection framework for DTH services. The gist of comments received from the stakeholders during the consultation process had been placed on the website of the Authority. The succeeding paragraphs briefly cover the issue-wise comments received from various stakeholders and set out the basis and rationale for the regulation.

D.1 Interconnection Agreements for DTH

12. While the comments received from the existing and potential DTH Operators were along the expected lines with all of them suggesting standard interconnection agreements as the desired regulatory framework, the broadcasters were divided on the issue. Most of the broadcasters were in favour of no regulation of interconnection agreements. One broadcaster favoured the standard interconnection agreements methodology and another recommended the Reference Interconnect Offer route. The consumer organisations and individuals were of the view that there is a need for regulating the interconnection agreements between broadcasters and DTH service providers through standard interconnection agreements. The Cable operators favoured the Reference Interconnect Offer.

D.2 Must Carry/ Carriage Fee

13. Most of the existing and potential DTH Operators were of the view that the clause requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis should be retained. Certain major broadcasters also expressed a similar view. However, certain smaller broadcasters wanted allocation of at least five channels to each broadcaster by a DTH Operator. This is understandable, because for a

broadcaster with less than five channels in his stable, such a formulation automatically implies "must carry", which is not the case with the existing clause requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis. The cable operators, an MSO and one of the potential DTH Operators opined in favour of removal of the clause requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis.

14. As regards regulation of carriage fee, there was near consensus that it should be left to the market forces. However, one of the potential DTH Operators recommended placing a ceiling on the amount of carriage fee. One of the smaller broadcasters and one association of the cable operators also wanted regulation of carriage fee.

E. Rationale for making amendment to the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004)

15. The Authority noted the fact that the two existing DTH Operators approached the Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) for getting access to popular content for their DTH platforms from some broadcasters in spite of clause 3.2 of the Interconnection Regulations clearly laying down that "Every broadcaster shall provide on request signals of its TV channels on non-discriminatory terms to all distributors of TV channels, which may include, but be not limited to a cable operator, direct to home operator, multi system operator, head ends in the sky operator...". In the present scenario, when more players are likely to launch their DTH platforms in the near future, it would be necessary to have a regulatory framework which will facilitate the existing as well as the new DTH Operators to get access to content of their choice and to ensure that the consumers can watch the channels of their choice on the DTH.

16. With the objective of having light touch regulation, the Authority has preferred Reference Interconnect Offer (RIO) over Standard Interconnection Agreements as the way of regulating interconnection agreements. This methodology gives the broadcaster the choice of framing their "Reference Interconnect Offer (RIO)" as per their business and marketing needs, within the broad guidelines decided by the Authority in its

regulations/ directions. At the same time it is necessary for the Authority to reserve to itself the power to intervene to protect the interests of consumers or service providers, or when an RIO is not in accordance with the interconnection regulation or to ensure growth of the sector. Accordingly, the RIO methodology has been provided in the regulations for regulating the interconnection agreements between broadcasters and DTH Operators.

17. The RIO methodology has been in vogue for cable television services being distributed through non-addressable systems (in non-CAS areas). However, DTH platforms are also addressable and this would remove any ambiguity relating to the subscriber base. Moreover, if most of the important terms and conditions are covered in the Reference Interconnect Offer, then the possibility of not being able to arrive at an interconnection agreement is greatly reduced. With this objective, the important terms and conditions to be compulsorily specified in the Reference Interconnect Offer have been enumerated in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007. Such terms and conditions inter alia relate to rates of channels and discounts, payment terms, security and anti-piracy requirements, subscriber reports and audit, tenure of agreement and termination of agreements etc. Thus, it is clear that the major financial terms and conditions (rate, discount, payment terms, and subscriber base) shall be covered in the Reference Interconnect Offers which have been left to the market forces in DTH services while making provisions for protecting interests of all stakeholders in DTH services. The other contentious issue of security and anti piracy measures shall also be covered. Therefore, the Reference Interconnect Offers are likely to result in cutting down delays in arriving at interconnection agreements.

18. Since the number of DTH Operators seeking interconnection from the broadcasters is limited (two at present), it has been mandated that the broadcasters shall intimate their Reference Interconnect Offers to all the DTH Operators. Since licensing of DTH Operators is a continuous process, the new DTH Operators shall have a right to make a request for the Reference Interconnect Offers and be provided with a copy of the same by the broadcasters. At the same time, for ease of access and ready reference purposes, it has been made mandatory for the Reference Interconnect Offers to be published on the websites of the broadcasters. Similarly, any changes in the Reference

Interconnect Offers are also required to be communicated to the DTH operators and published on the website. The DTH operators have also been given the option to seek modifications in the existing interconnection agreements so as to be in consonance with the Reference Interconnect Offer published by a broadcaster under these regulations.

19. The Reference Interconnect Offer is only a methodology for arriving at interconnection agreements and the service providers and broadcasters can also enter into an interconnection agreement on mutually agreed terms and conditions. However, since the over riding principle is provision of signals on non discriminatory basis, the broadcaster shall be required to offer the same terms and conditions to any other DTH Operators if so requested by such other DTH Operators.

At the same time, principle of non discriminatory access implies that the DTH Operators who have already signed interconnection agreements with the broadcasters should also be given an option to enter into new interconnection agreements based on the Reference Interconnect Offer so published by the broadcaster.

20. For the Reference Interconnect Offer methodology to be an effective tool for access of content, it is important to specify a time limit within which the interconnection agreement based on the Reference Interconnect Offer shall be signed by the broadcaster with the DTH operator. Accordingly, a time limit of forty five days has been specified in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007.

21. The provisions relating to the situation where both parties namely the broadcaster and the DTH Operator jointly approach the Authority requesting for facilitation of entering into an interconnection agreement, are based on similar provisions in the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007 issued by the Authority on the 7th June, 2007. The provisions are merely for facilitation of an interconnection agreement by the Authority on a joint request of both the parties with a view to minimize litigation. These provisions do not in any way affect the legal rights and remedies available to the parties otherwise under any law for the time being in force.

22. There has been a persistent demand from the DTH service providers that Authority should facilitate access to content without the compulsion of carrying all the channels bundled together which in their view are relatively less popular. Even on a complaint relating to increase in tariff of DTH services, a DTH service provider has indicated bundling of channels as a reason for higher tariff. In this background, it was felt necessary that declaration of a-la-carte prices of channels in Reference Interconnect Offers should be mandated. Without the mandating provision of channels on a-la-carte basis, the very purpose of amendments in the existing interconnection regulation will be defeated.

23. The Hon'ble TDSAT had observed in its order dated the 31st March, 2007 in Petition No. 189(C) Of 2006 in the case of Tata Sky Limited Versus Zee Turner Limited and others, while discussing clause 7.6 of the terms and conditions of the DTH licence agreement, requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis, that :-

"...If a DTH operator has to take all the channels of every broadcaster, it may not be physically possible to do so. Moreover, if every channel has to be taken it means that it will have to be paid for. This will increase the cost for the DTH operator. Ultimately, the cost will get passed on to the consumer. If DTH becomes expensive consumers will keep away from it. It will not be able to compete with CAS or cable. Thus, such an interpretation of clause 7.6 may be anti consumer..."

24. Apart from increase in the cost of direct to home services to the subscribers, there is an important technical reason for mandating a-la-carte availability of channels to direct to home operators. There is a technical limitation on the number of channels that a direct to home operator can carry on its platform. Presently 270 channels are permitted under uplinking or downlinking guidelines in the country. The transponder capacity on a satellite is limited and a direct to home operator can beam around 12 channels per transponder, depending on the compression technology used. The availability of transponder space would limit the number of channels offered by the DTH service providers. Insat 4A and Insat 4B have a capacity of 12 Ku band and 12 C-band transponders each. Therefore, it is not technically possible for a direct to home operator using an Insat satellite to offer all the 270 channels. The Hon'ble TDSAT had also

observed in its order dated the 31st March, 2007 in Petition No. 189(C) Of 2006 in the case of Tata Sky Limited Versus Zee Turner Limited and others, that:

"...It is relevant and important that a DTH operator may not like to take all the channels of a particular broadcaster and exhaust its transponder capacity by taking unwanted channels. After all, the DTH operator is in business and it has to watch its business interest..."

25. However, provision of channels on a-la-carte basis also necessitates the need for regulating the relationship between the prices of channels on a-la-carte basis and bouquet prices so as to ensure that the a-la-carte choice of channels does not become illusory on account of perverse pricing of channels and bouquets of channels. Accordingly, the formulation given by the Authority for co-relation between a-la-carte and bouquet prices for commercial subscribers of cable television services has been adopted for DTH Operators also.

26. The DTH Operators also sought the freedom to package channels of bouquets opted by them. They justified their demand by citing the need for packaging the content in such a manner that helped them in localising the content to suit the local tastes of different regions of the country. The Authority has decided to permit the same. At the same time, the interests of the broadcasters have been protected by mandating that the highest subscriber base for any channel in a bouquet shall be the basis for payment to the broadcaster for the entire bouquet.

27. Clause 7.6 of the terms and conditions of the DTH licence agreement requiring provision of access to various content providers/channels on a non-discriminatory basis is within the scope of the terms and conditions of the DTH licensing provisions for which the competent authority is Government of India (Ministry of Information & Broadcasting). Therefore, amendment of the said clause is outside the purview of this regulation on interconnection issues. Accordingly, this issue is not being discussed further in this Explanatory Memorandum.

28. While making The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007, the Authority has made all

efforts to maintain equity amongst the interests of various stakeholders, namely, the broadcasters, the DTH operators and the direct to home subscribers and to promote growth in the direct to home service, being one of the telecommunication service.